संख्या-फिन्न(सी)(ए-(3)-20/77-II
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (विनियम) विभाग ।
दिनांक शिमला-171002

11/10 1979 12/10/79

कार्यालय ज्ञापन
=============

विषय:- पेन्शन नियमों में संशोधन-मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान की देर से अदायगी किए जाने पर ब्याज का भुगतान ।
==

मुझे भारत सरकार, गृह मन्त्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या-एफ-7(1)(पी०यू०/79 दिनांक 11-7-79 की एक प्रतिलिपि भेजते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आदेश देते है कि उसमें अन्तर्निविष्ट निर्णय हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे ।

गृह मन्त्रालय के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैराग्राफ -2 में निर्दिष्ट वित्त मन्त्रालय के 28-2-76 तथा 15-2-79 के कार्यालय ज्ञापन वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-2-2/72-फिन्न(रेग)III- दिनांक 24-4-79 तथा फिन्न(सी) ए-(3)20/77, दिनांक 17-4-79 द्वारा परिचालित किए गए थे ।

(राम चन्द्र कौशिश)
उप सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

सेवा में,

हिमाचल प्रदेश सरकार के
समस्त प्रशासनिक विभाग ।

संख्या-फिन्न(सी)-ए-(3)20/77-II- दिनांक शिमला-171002 11/10 -1979

प्रतिलिपि प्रेषित है :-

1. डिविजनल कमीश्नर, हिमाचल प्रदेश उत्तर खण्ड शिमला
2. डिविजनल कमीश्नर, हिमाचल प्रदेश दक्षिण खण्ड धर्मशाला ।
3. लाईजन ऑफिसर हिमाचल प्रदेश गोल्फ लिंक नई दिल्ली-110003
4. हिमाचल प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष ।
5. रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला ।
6. हिमाचल प्रदेश के समस्त जिला तथा सैशन जज ।
7. हिमाचल प्रदेश के समस्त जिलाधीश ।
8. हिमाचल प्रदेश के समस्त खजाना अधिकारी/उप खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी ।
9. हिमाचल प्रदेश के खजाना तथा लेखा संगठन के प्रशासनिक अधिकार में सभी लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी/
10. परीक्षक स्थानीय लेखा परीक्षा वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-2

-----2/-----

S.8/3

-2-

11: निरीक्षक अधिकारी, [illegible] तथा लेखा [illegible] सिविल बाजार [illegible], हिमाचल प्रदेश ।

12: सहायक निदेशक, (वित्तीय प्रशासन) हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फागोबरा, शिमला-12

13: श्री महाकर प्रधान, हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी म 183 अंगारा बाजार कुल्लू, (हि०प्र०)

14: श्री हरि सिंह, महा सचिव, हिमाचल प्रदेश, अराजपत्रित क महा संघ 11 गवर्नमेन्ट कालोनी, ऊना, (हि०प्र०)

15: श्री एन०एन०कैथना, संयुक्त सचिव, हिमाचल प्रदेश अराजप कर्मचारी महासंघ पाइन ग्रोव, शिमला-171002

उप सचिव
हिमाचल प्रदेश सरका

संख्या-फिन्न(सी)-ए(3)20/77-दिनांक-शिमला-171002 11/10 सितम्ब

एक प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :-

1: सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड शिमला-4

2: सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश शिमला-1

3: रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5

4: हिमाचल प्रदेश के सभी सहकारी निगम ।

संख्या-फिन्न(सी)-ए-(3)20/77- दिनांक शिमला-171002 11/10 सितम्बर-

एक प्रतिलिपि (40 फालतू प्रतिलिपियों सहित) महालेखाक हिमाचल प्रदेश, पेंशन(आर) शाखा, शिमला को भेजी जाती है ।

उप सचिव
हिमाचल प्रदेश सरका

प्रतिलिपि :-

1: वित्त विभाग के सभी अनुभागों को (5 प्रतिलिपियों

2: गार्ड फाईल ।

----000----

/शि व/
22-9-79

(3)

(3)

Copy of letter No.F.7(1)-PU/79 dated 11th July, 1979 from Under Secretary to the Govt. of India Ministry of Home Affairs Department of Personnel & A.R. New Delhi addressed to All Ministries/ Departments of the Government of India & copy to ends All States Governments and Union Territories Administration. & others:-

Subject:- Payment of interest on delayed payment of Death-cum-Retirement Gratuity.

The Staff side made the suggestion in the National Council (JCM) that interest may be paid to retired employees if payment of D.C.R.G. is delayed. The matter has been examined and the President is pleased to decide that interest may be allowed on delayed payments of Gratuity at the rate of 5 percent per annum for the period beyond three months after the gratuity becomes due and would be payable till the end of the month preceding the month in which the payment is actually made. The interest will be allowed only where it is clearly established that the payment of D.C.R.G. was delayed on account of administrative lapse or for reasons beyond the control of the Government servant concerned. Each case of payment of interest shall be considered by the Administrative Ministry in consultation with the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms and the payment of interest will be authorised through a Presidential sanction. In all cases where interest has to be paid, action should be taken to fix responsibility for the delay and disciplinary action should be taken against the officer responsible for it.

2. A detailed time table for finalising pension cases has been laid down in the Ministry of Finance O.M.No.F.11(3)-EV(A)/76 dated 28.2.1976. Under the rules gratuity becomes due immediately on retirement. In case of a Government servant dying in service, a detailed time table for finalising ~~paid~~ pension and D.C.R.G. has been laid down in Finance Ministry's O.M.No.F.11(9)-EV(A)/77 dated 15.2.1979.

3. Where disciplinary or judicial proceedings against a Government servant are perding on the date of his retirement, the provisional pension is authorised under Rule 65 or Rule 74 of C.C.S.(Pension)Rules, 1972. No gratuity is paid in such cases until the conclusion of the proceedings and the issue of final orders thereon. The gratuity if allwed to be drawn by the competent authority on the conclusion of the proceedings will be deemed to have fallen due on the date of issue of orders by the competent authority.

4. Nothing contained in this O.M. will apply to the payment of arrears of gratuity which may become due as a result of enhancement of the emoluments after retirement or liberalisation in the C.C.S.(Pension)Rules, 1972 from a date prior to the date of retirement of the Government servant.

....2/-

(4)

5. These orders shall take effect from the date of issue of this O.M. The cases of those Government servants who retired/died while in service before this date would also be covered if D.C.R.G. has not been paid as on the date of issue of this O.M. and there has been delay in its payment beyond three months of the date of their retirement/death but the interest would be payable in such cases only from the date of the issue of this O.M. or three months from the date of retirement/death whichever date is later.

6. In so far as persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders have been issued after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

-.-.-.-.-.-